www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

आपका भरोसा, हमारी ताकत

RNI No. : DELHIN/2016/70240

2 अमर्यादित नहीं हो सकती है अभिव्यक्ति की...

3 ईवीएम डिमॉन्सट्रेशन सेंटर का उद्घाटन, आम जनता...

4 हल्की बारिश से राजौंद की सड़क बनी तालाब

वर्ष: 9 | अंक: 263 | दिल्ली, गुरुवार, 17 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, राहुल और खरगे ने पीएम को लिखा पत्र

जम्मू-कश्मीर (एजेन्सी)। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाए। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों से जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह माँग जायज होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि जहाँ अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में बेमिसाल है।

एक साथ हुआ 7 लोगों की जिंदगी का दर्दनाक अंत

जम्मू-कश्मीर (एजेन्सी)। जम्मू-कश्मीर के डोडा में चिनाब घाटी के बार कुछ ही पलों में शांत सड़क पर तेज-तेज से चीख पुकार मच गये। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और देखा कि एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया था। एक टेंपो ट्रेवलर खाई में गिर गया था। साथ ही मौके पर 7 लोगों की मौत भी हो गयी थी। इशके अलावा घायल लोग कुछ सड़क के किनारे पड़े थे तो कुछ खाई में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये हादसा बेदल दर्दनाक था। आइये जानके है पूरी अपडेट क्या है- डोडा जिले में मंगलवार को एक यात्री वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से एक महिला और एक नाबालिग लड़की समेत सात लोगों की मौत हो गई जबकि 17 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि वाहन में उसकी क्षमता से अधिक लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना डोडा शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर पोंडा के पास डोडा-भर्थ मार्ग पर हुई।

असम के डिब्रूगढ़ में हाइड्रोकार्बन मिला: मुख्यमंत्री शर्मा

असम (एजेन्सी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने डिब्रूगढ़ जिले में नामरूप बोरहाट-1 कुएं में हाइड्रोकार्बन की खोज की है, जिसमें राज्य सरकार की अहम हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री ने इस खोज को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नामरूप बोरहाट-1 कुएं में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी पाई है, इसमें असम सरकार की अहम हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खोज तेल ड्रिलिंग में सफल निवेश और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान सुनिश्चित करती है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, यह खोज असम को पहला प्रत्यक्ष तेल उत्पादक राज्य बनाती है, अन्वेषण प्रयासों को सफल बनाती है, असम को राजस्व और रॉयल्टी से सशक्त बनाती है और देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 97वें स्थापना दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही पुरस्कार समारोह और विकसित कृषि प्रदर्शनी में भाग लेते हुए। (स्त्रोत: पीआईबी)

डेंगू प्रकोप: चालान काटने से पहले दो बार चेतावनी दी जाए: सीएम रेखा गुप्ता

फॉगिंग भी जल्द शुरू की जाए, ताकि डेंगू पर कंट्रोल बना रहे: सीएम

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। दिल्ली सचिवालय में मौजूद इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मच्छरों की उत्पत्ति पर चालान काटने से पहले दो बार चेतावनी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग (धुआं छोड़ना) को तय समय से पहले शुरू कर दी जाए, ताकि कीट जनित रोगों का फैलाव पहले से ही रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन रोगों को लेकर आगामी दो माह बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी जरूरी है। इसके लिए जागरुकता, निगरानी व कार्रवाई जरूरी है।

इस बैठक में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कीट जनित बीमारियों का प्रकोप अभी दिल्ली में फैला नहीं है, इसके बावजूद हमें सतर्क और एक्शन में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सारे उपाय करें और इस अभियान में लोगों को भी शामिल करें। इसके लिए सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों, पार्कों, खुले स्थानों, अस्पतालों आदि में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के विशेष प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन घरों या स्थानों में मच्छर की उत्पत्ति पाई जाती है, वहां चालान काटने से पहले दो बार चेतावनी दी जाए, ताकि लोग जागरुक हो जाए और मच्छरों से बचाव के उपाय खुद ही तलाशें। बैठक में अफसरों ने बताया कि मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए सितंबर माह में फॉगिंग की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही फॉगिंग अभियान शुरू किया जाए, ताकि मच्छरों का प्रकोप रुके और लोगों का विश्वास बढ़े कि सरकार व शासन डेंगू व अन्य बीमारियों की रोकथाम में गंभीरता से जुटा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाओं या मशीनरी आदि की कमी नहीं रहनी जाए, अगर कुछ समस्या आए तो सीधे हमें सूचित करें। इन बीमारियों से बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि अब तक 5,09,524 घरों में फॉगिंग और मच्छरनाशक स्प्रे का कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा, 71,086 घरों में मच्छरों के लार्वा पाए गए जिन्हें मौके पर ही नष्ट किया गया। इस कार्य के माध्यम से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत दिल्ली के 279 स्थानों पर लावीवोरस मछलियां छोड़ी गई हैं, जो मच्छरों के लार्वा को प्राकृतिक रूप से खत्म करने में सहायक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू जैसे रोगों से बचाव केवल सरकारी काम नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए हर स्तर पर एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। जनता को जागरूक करना, सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई सुनिश्चित करना और तकनीक के माध्यम से निगरानी को और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है।

सीएम ने दिए गुरुग्राम को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश, पार्षदों से मांगा सक्रिय सहयोग

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम शहर की स्वच्छता को बनाए रखने और इसे निरंतर बेहतर बनाने के लिए निगम पार्षदों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए पार्षदों से आह्वान किया कि वे निगम अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करें।

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने पार्षदों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी जनसमस्याओं के समाधान में कोताही बरतता है, तो वे सीधे मुख्यमंत्री से फोन पर संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में 18 परिवाद रखे गए, मुख्यमंत्री ने 15 परिवादों का निपटारा करते हुए तीन मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों से आगामी बैठक में स्टेट्स रिपोर्ट लेकर आने के निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान अपने चिर-परिचित संवेदनशील अंदाज में उन परिवादियों से स्वयं फोन पर संपर्क किया, जिनके मामले पहले ही निपटाए जा चुके थे, किंतु वे बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परिवादी से समाधान की स्थिति के बारे में जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि वे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं।

बैठक में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के पूर्व सदस्य एडवोकेट रविन्द्र जैन ने बताया कि सदर बाजार में जैन मंदिर के नजदीक जमा कूड़े को उठाने के लिए कई बार सफाई कर्मियों को संपर्क किया गया, लेकिन अभी भी समस्या का निवारण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने निगम कर्मियों की कार्यशैली से नाराजगी जताते हुए संबंधित क्षेत्र के सैनेटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के निवारण के लिए अपनी कार्यशैली में बदलाव करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

बैठक में गाँव बहोड़ा कला से आए एक शिकायतकर्ता ने बताया कि गाँव में किसी व्यक्ति ने श्मशान घाट के सरकारी रास्ते पर कब्जा किया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे त्वरित रूप से इस मामले में कारवाई कर चिह्नित रास्ते की पैमाइश करवाएं, यदि संबंधित व्यक्ति ने सरकारी रास्ते पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। बैठक में जैकबपुरा से आए शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके वार्ड में सीवर ओवरफ्लो से जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है। नगर निगम में विभिन्न स्तर पर शिकायत करने के बाद भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता से जुड़ी इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निगम आयुक्त को शिकायत के संदर्भ में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारी समस्याओं के निवारण की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर उन्हें राहत प्रदान करने का कार्य करें।

इस अवसर पर जिला परिषद की चेयरपर्सन दीपाली चौधरी, गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा, प्रधान सलाहकार श्री डीएस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्री श्यामल मिश्रा, उपायुक्त श्री अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कांवड़ यात्रा में लिया भाग, ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में अर्पित की पुष्पांजलि

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चांदनी चौक में कावड़ यात्रा में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित कर इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दीं। श्री गुप्ता ने कांवड़ियों की आस्था और भक्ति भावना की सराहना की और कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी सांस्कृतिक एकता, श्रद्धा और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है।

सीएम की ओर से केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ मुलाकात

आरडीएफ और मंडी शुल्क के तौर पर राज्य के हिस्से के 9000 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने की मांग

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली/चंडीगढ़। मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने ग्रामीण विकास कोष (आर.डी.एफ.) और मंडी शुल्क के रूप में पंजाब के हिस्से के 9000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को तुरंत जारी करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से हस्तक्षेप की मांग की।

मुख्यमंत्री ने शाम यहां श्री जोशी के साथ उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। मुख्य मंत्री ने खरीफ 2021-22 से ग्रामीण विकास कोष का भुगतान न होने और खरीफ सीजन 2022-23 से मंडी शुल्क के कम भुगतान का मुद्दा उठाया।

मुख्य मंत्री ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसके तहत ग्रामीण संपर्क सड़कों, मंडियों के बुनियादी ढांचे, मंडियों में भंडारण क्षमता बढ़ाने और मंडियों के मशीनीकरण के लिए फंड खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निदेर्शों के अनुसार पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम-1987 में आवश्यक संशोधन भी कर लिया था, फिर भी सावनी 2021-22 से राज्य सरकार को आर.डी.एफ. नहीं मिला। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 7737.27 करोड़ रुपए का आर.डी.एफ. और 1836.62 करोड़ रुपए का मंडी शुल्क केंद्र सरकार के पास लंबित है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इन फंड्स के जारी न होने के कारण राज्य गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड/ग्रामीण विकास बोर्ड अपने कर्जों/देनदारियों का भुगतान करने, मौजूदा ग्रामीण बुनियादी ढांचे की मरम्मत/रखरखाव करने और समग्र ग्रामीण विकास के लिए नया बुनियादी ढांचा स्थापित करने में सक्षम नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से अधिक जनहित में राज्य को बकाया फंड जल्द से जल्द जारी करने की अपील की।

मुख्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जोर देकर कहा कि पिछले दो वर्षों से प्रांत में ढके हुए भंडारण स्थानों की निरंतर कमी है। उन्होंने कहा कि खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-24 के दौरान मिलिंग वाले चावल के लिए जगह की कमी के कारण डिलीवरी की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ानी पड़ी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन के दौरान मिलों में बहुत हंगामा हुआ था और शुरू में मिलर धान उठाने और भंडारण करने से हिचक रहे थे, लेकिन इस मुद्दे को राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से हल कर लिया था।

मुख्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 में भी एफ.सी.आई. को दिए जाने वाले 117 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) चावल में से 30 जून, 2025 तक केवल 102 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी दी जा चुकी है, जबकि 15 लाख मीट्रिक टन की डिलीवरी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 महीनों में औसतन 6.67 एल.एम.टी. की दर से केवल 80 एल.एम.टी. चावल ही राज्य से उठाए गए या बाहर भेजे गए हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि एफ.सी.आई. ने जून, 2025 के महीने के लिए पंजाब से 14 एल.एम.टी. चावल की ढुलाई की योजना बनाई थी, लेकिन वास्तव में केवल 8.5 एल.एम.टी. चावल का ही निपटान हुआ है।

इसके अनुसार, मुख्य मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2025 में कम से कम 15 लाख मीट्रिक टन चावल की ढुलाई की आवश्यकता है ताकि 31 जुलाई, 2025 तक मिलिंग पूरी की जा सके।

नशे पर नियंत्रण के लिए तय करें बीट अधिकारी की जिम्मेदारी: इंद्राज

समाज कल्याण मंत्री ने बीट अफसर की जवाबदेही तय करने के लिए पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बुधवार को नशामुक्ति अभियान की प्रगति को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिले के डीएम, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के साथ समीक्षा बैठक की।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि उन्होंने नशे के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए नशे की बिक्री वाले स्थानों पर बीट अफसर की जवाबदेही तय करने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र भी लिखा है। समाज कल्याण मंत्री ने नशे पर नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग को डार्क स्पॉट्स का चयन करने और चयनित जगहों पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने एवं नशे के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चयनित डार्क स्पॉट्स की सूची पुलिस विभाग साझा भी करे ताकि उन जगहों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाएं। श्री इंद्राज ने कहा कि उन्होंने मेडिकल स्टोर्स व अन्य जगहों पर ऐसे उत्पादों की बिक्री में सावधानी के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, जो नशे के लिए प्रयुक्त हो रही हैं। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली

मंत्री ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिले के पुलिस-प्रशासन, संबंधित विभागों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

को नशा मुक्त और विकसित बनाने के लिए जनसहयोग और विभागीय समन्वय से काम करें। नशे पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है कि युवाओं और किशोरों को नशे की गिरफ्त से बचाने के उपायों और प्रयासों पर अधिक जोर दिया जाए। इसके लिए शैक्षणिक संस्थान पुलिस और जनसहयोग की मदद से अपने परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाएं। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में वालन्टियर्स तैयार कर नशे के खिलाफ लड़ाई में प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों से आग्रह भी किया है कि अपने परिसर में 'नशा मुक्ति क्लब' बनाएं और परिसर को ड्रग फ्री घोषित करें।

कैबिनेट मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि पार्कों में ओपन जिम की सुविधा विकसित करें, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के विकल्प बढ़ाएँ, नए डिएडिक्शन सेंटर शुरू करें और जागरूकता कार्यक्रमों खासकर अभिभावकों को ड्रग लेने वाले बच्चों के लक्षणों को लेकर जागरूक करें।

सम्पादकीय

समानता रिपोर्ट में बेहतरी की ओर भारत

इसे संयोग कहें या कुछ और, जिस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दिनों जोड़े गए शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को लेकर बहस हो रही है, ठीक उसी वक्त आई विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारतीय समाज को ज्यादा समतामूलक बताया है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस रैंकिंग में चोटी के चार देशों में शामिल हो गया है, जबकि दुनिया की नंबर एक और नंबर दो अर्थव्यवस्थाएं यानी अमेरिका और चीन इससे पीछे हो गए हैं। भारत से आगे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। दिलचस्प यह है कि जिस समय यह रिपोर्ट आई है, ठीक उन्हीं दिनों ऑक्सफैम जैसी दूसरी एजेंसियों की ओर से आई रिपोर्टों के हवाले से भारत में बढ़ती आर्थिक आर्थिक असमानता को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में विश्व बैंक की इस रिपोर्ट का आना और उसके समानता सूचकांक में भारत का बेहतर प्रदर्शन करना सुखद आश्चर्य का कारण तो बनता ही है। विश्व बैंक के समानता सूचकांक को गिनी सूचकांक भी कहा जाता है। एक तरह से यह आर्थिक विकास को सामाजिक समानता से जोड़ने का सूचकांक है। इस आंकड़े के अनुसार, भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। इस सूचकांक के अनुसार, भारत सामान्य से कम असमानता श्रेणी में है। मानकों के अनुसार, इस श्रेणी के लिए स्कोर 25 से 30 के बीच होता है। यह कम असमानता वाले समूह के मानक से कुछ ही ज्यादा है। इस श्रेणी में स्लोवाक गणराज्य शामिल है। स्लोवाक का गिनी इंडेक्स 24.1 है। इसी तरह दूसरे स्थान पर रहे सोवियत संघ के पूर्व हिस्से और मौजूदा स्लोवेनिया देश का सूचकांक 24.3 है। इसके बाद 24.4 अंकों के साथ बेलारूस है। इन तीनों के बाद भारत का नंबर है। गौरतलब है कि विश्व बैंक ने दुनिया के 167 देशों का गिनी इंडेक्स जारी किया है। इनमें भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ.30 देश 'सामान्य से कम' असमानता वाली श्रेणी में आए हैं। जिनमें अत्यधिक लोक कल्याण वाले अनेक यूरोपीय देश जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम और पोलैंड शामिल हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसा धनी देश भी शामिल है। इस सूचकांक के लिहाज से भारत का प्रदर्शन विगत के डेढ़ दशक की तुलना में बहुत बेहतर है। साल 2011 में भारत का गिनी सूचकांक 28.8 था। साल 2022 में यह 25.5 पर पहुंच गया। गिनी सूचकांक के जरिए यह समझने की कोशिश की जाती है कि देश विशेष के घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति और उसके उपभोग के वितरण में कितनी समानता है। इसे शून्य से लेकर 100 के सूचकांक के स्तर पर मापा जाता है। इस सूचकांक के अनुसार, जिस देश का स्कोर शून्य है, उसका मतलब है कि उस देश में पूरी तरह समानता है यानी आय का वितरण पूरे नागरिकों में समान है। इस सूची में 100 स्कोर का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय और संपत्ति है और वही सबसे ज्यादा उपभोग करता है, जबकि दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि उस देश विशेष में पूरी तरह असमानता व्याप्त है। मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जिस देश का गिनी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस देश में उतनी ही असमानता होगी। विश्व बैंक का मानना है कि गिनी इंडेक्स में भारत की मजबूत स्थिति की वजह उसके गरीबी हटाओ उपाय हैं। जिनके जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बीते दशक में 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई है। विश्व बैंक ने गरीबी के लिए रोजाना 2.15 अमेरिकी डॉलर से नीचे की आय को रखा है। इस लिहाज से भारत में 2011-12 के दौरान करीब 16.2 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे, उनकी संख्या में साल 2022-23 में घटकर सिर्फ 2.3 प्रतिशत रह गई है। भारत में समानता लाने में मोदी सरकार की योजनाओं का बहुत योगदान है। इसमें नई योजनाएं हैं और पुरानी का बेहतर कार्यान्वयन भी है। इन योजनाओं के जरिए लोगों तक आर्थिक पहुंच में सुधार करना, राज्य की ओर से दिए जा रहे कल्याणकारी फायदों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और इस पूरी प्रक्रिया में समाज के कमजोर और कमजोर प्रतिनिधित्व वाले समूहों का सहयोग करना है। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना को पहले स्थान पर रखा जा सकता है। जिस योजना के तहत 25 जून, 2025 तक 55.69 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास जन धन खाते थे। इनके जरिए ना सिर्फ लोगों को राज्य की ओर से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सीधे पहुंच रहा है, बल्कि वित्तीय कामकाज के लिए बैंकों तक इन लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। आधार और डिजिटल पहचान के जरिए कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हुई है। तीन जुलाई, 2025 तक देश के 142 करोड़ से अधिक लोगों के आधार कार्ड जारी किए जा चुके थे। राज्य के कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान और सब्सिडी आदि को अब सीधे लोगों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। इसकी वजह से देश की बचत बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार, मार्च 2023 तक देश की संचयी बचत 3.48 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी। जाहिर है कि इनमें से ज्यादातर लोगों का पैसा प्रत्यक्ष और सीधे खातों तक वित्तीय मदद पहुंच रहा है।

जयंती

बेगम आबिदा अहमद

जन्म-17 जुलाई, 1923-मृत्यु: 7 दिसम्बर, 2003) भारत के पाँचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी थीं। ये बेहद सुलझे विचारों वाली एक शिक्षित महिला के रूप में जानी जाती थीं। आबिदा बेगम सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बड़े उत्साह के साथ भाग लेती थीं।

पुण्यतिथि

इंदुलाल याज्ञिक

जन्म-22 फरवरी, 1892, खेड़ा ज़िला, गुजरात; मृत्यु-17 जुलाई, 1972) 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' में भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। वे गुजरात प्रदेश के निर्माताओं में से एक और 'ऑल इंडिया किसान सभा' के नेता थे। उन्होंने 'गुजरात विद्यापीठ' की स्थापना की योजना बनाई थी। इंदुलाल याज्ञिक गुजरात की सत्याग्रह कमेटी के सचिव भी बनाये गए थे। वर्ष 1923 में उन्हें गिरफ्तार करके यरवदा जेल में महात्मा गाँधी के साथ बंद किया गया था। यह बात भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति 'महागुजरात सेवा ट्रस्ट' को दान कर दी थी।

कल मिलेंगे

एक युग था जब लोग अपने घर के दरवाजे पर लिखते थे-अतिथि देवो भव:,
फिर लिखा-शुभ लाभ,
फिर लिखा-यू आर वेलकम,
और अब-कुत्तों से सावधान.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

अमर्यादित नहीं हो सकती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह पर नागरिक समाज को न केवल चिंतन-मनन करना चाहिए अपितु उसका अनुकरण भी करना चाहिए-नागरिकों को अपनी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत समझनी चाहिए और इसके साथ-साथ स्व-नियंत्रण और संयम का पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए

-लोकेन्द्र सिंह

जब हम विरोध, आलोचना और असहमति के वास्तविक स्वरूप को भूलते हैं तब हमारी अभिव्यक्ति घृणा और नफरत में बदल जाती है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय विचार के संगठनों एवं कार्यकताओं पर टिप्पणी का स्वर ऐसा ही दिखायी पड़ रहा है, जो अमर्यादित है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही अमर्यादित अभिव्यक्ति के मामलों की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं है, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। इस पर किसी प्रकार के बाहरी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि इसी प्रकार अमर्यादित लिखा-पढ़ी, बयानबाजी और कार्टूनबाजी जारी रही तब समाज में वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव को फैलने से रोकने के लिए कुछ न कुछ युक्तियुक्त प्रबंध करने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी को भी अमर्यादित और असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को भी समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक मयार्दा है, उसे लांघना किसी के भी हित में नहीं है। उचित होगा कि नागरिक समाज इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करे। सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल समाज में नफरत और विघटन को जन्म दे सकता है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से बोलें, संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।

हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने भी कहा है कि जो व्यवहार हम अपने लिए अपेक्षित करते हैं, वही व्यवहार हमें सामने वाले के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने आया वजाहत खान का मामला ऐसा ही है, जिसमें हिन्दू देवी पर तो आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है लेकिन इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा है। जब पलटकर किसी ने हिन्दू धर्म का अपमान करने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, तो वह न्यायालय में पहुँच गया है। याद हो कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भावावेश में आकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि जब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो उसने बिना शर्त माफी भी माँग ली और अपना वह वीडियो भी हटा लिया था। लेकिन इसके बावजूद वजाहत खान ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। हालांकि ऐसा करते समय वजाहत खान ने अपने गिरेबां में झांककर नहीं देखा कि वह क्या कर रहा है? जब आप अपनी आस्था पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करते तब आपको दूसरों के देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने का अधिकार किसने दे दिया है? अच्छा ही हुआ कि वजाहत खान जैसों को आईना दिखाने के लिए हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। अब उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मोल समझ आएगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि लोगों को हेट स्पीच क्यों अटपटे और गलत नहीं लगते हैं। ऐसे कंटेंट पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही लोगों को भी ऐसे नफरत भरे कंटेंट को शेयर करने और लाइक करने से बचना चाहिए।

इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के बेहद आपत्तिजनक कार्टून को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने कार्टूनिस्ट की मानसिकता पर प्रश्न उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बनाए गए इस आपत्तिजनक कार्टून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आजकल कार्टूनिस्ट और स्टैंडअप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या ये लोग कुछ भी बनाने और बोलने से पहले सोचते नहीं है? न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार के घृणित व्यंग्य चित्रों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई परिपक्वता नहीं है। ये वास्तव में भड़काऊ है। याद हो कि इस कार्टूनिस्ट के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय भी फटकार लगा चुका है। उच्च न्यायालय ने जब कार्टूनिस्ट की जमानत याचिका खारिज की तो उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन यहाँ भी उनके कृत्य पर कोई राहत नहीं मिली है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई कलात्मक अभिव्यक्ति भी नहीं है। अपनी वैचारिक और राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए इस प्रकार के लोग कला को भी बदनाम करते हैं, जो अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम हैं। मजेदार तथ्य यह कि हेमंत मालवीय का बचाव कर रहे उनका भी वकील यह मानता है कि हाँ, ये घटिया कार्टून है। लेकिन क्या ये अपराध है? नहीं, यह अपराध नहीं हो सकता। यह आपत्तिजनक हो सकता है लेकिन अपराध नहीं। अब यह अपराध है या नहीं, यह तो न्यायालय तय करेगा लेकिन मालवीय का वकील कम से कम यह तो स्वीकार ही कर रहा है कि कार्टून घटिया है। आरोप यह हैं कि उनका कार्टून प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रीय संगठन का अपमान ही नहीं करता है अपितु सांप्रदायिकता को भी भड़काता है। हेमंत मालवीय की शिकायत दर्ज करानेवाले सामाजिक कार्यकर्ता विनय जोशी आरोप लगाए हैं कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा। उनकी ओर से दर्ज करायी गई एफआईआर में कई आपत्तिजनक पोस्ट का उल्लेख किया गया है, जिनमें भगवान शिव पर कथित रूप से अनुचित टिप्पणियों के साथ-साथ मोदी, आरएसएस कार्यकताओं और अन्य लोगों के बारे में कार्टून, वीडियो, तस्वीरें और टिप्पणियाँ शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत मालवीय ने पहली बार आपत्तिजनक कार्टून नहीं बनाया था, बल्कि यह उनका नियमित अभ्यास है। न्यायालय के अनुसार, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह पर नागरिक समाज को न केवल चिंतन-मनन करना चाहिए अपितु उसका अनुकरण भी करना चाहिए-नागरिकों को अपनी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत समझनी चाहिए और इसके साथ-साथ स्व-नियंत्रण और संयम का पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को कहा है कि वे नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकें। हालांकि न्यायालय ने किसी भी प्रकार की सेंसरशिप की बात से इनकार किया। यानी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने वकीलों एवं सरकारों से सुझाव भी माँगे हैं। हालांकि यह राह बहुत कठिन है कि सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध भी न लगाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरती सोच पर लगाम भी लगा ले। इस दिशा में यदि कहीं कोई राह दिखायी देती है, तो वह जागरूक नागरिक समाज है। समाज को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे आना होगा। जब नफरती भाषण करनेवालों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा हतोत्साहित किया जाने लगेगा, तब बहुत हद तक इस पर नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय विचार के कार्यकताओं के धैर्य की सराहना करनी होगी कि वे नफरत की बौछारों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि अन्य विचार या संप्रदाय के प्रति अमर्यादित बयानबाजी होती है, तो तत्काल उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। शायद इसलिए ही सबने हिन्दू धर्म, हिन्दू संगठन और हिन्दू समाज को पंचिंग बैग समझ लिया है। इस पर लगाम लगनी ही चाहिए। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस आग्रह का पालन व्यापक स्तर पर हम सबको करना चाहिए, जिसमें न्यायालय ने कहा कि लोग स्वयं से जिम्मेदारी निभाएं और अपनी बातों में संयम बरतें।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

डिजिटल-क्रांति से ही नकली नोटों पर नियंत्रण संभव

प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल क्रांति न केवल नकली नोटों को नियंत्रित करने का बल्कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नेस्तनाबूद करने का सशक्त माध्यम है। यह मोदी की दूरदृष्टि एवं नये भारत-विकसित भारत के विजन की विजय है, उनके ही विचारों में डिजिटल लेन-देन केवल तकनीक नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। आज के भारत की अर्थव्यवस्था एक निर्णायक दौर से गुजर रही है

-ललित गर्ग

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में जारी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने न केवल अर्थव्यवस्था को, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की जागरूकता को भी झकझोर कर रख दिया है। आरबीआई के गवर्नर द्वारा संसदीय समिति में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 500 रुपए के लगभग 1.8 लाख नोट नकली पाए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक हैं। यह संख्या किसी सामान्य अपराध की नहीं, बल्कि राष्ट्र के विरुद्ध एक षड्यंत्र की कहानी कहती है। जो यह दशार्ता है कि कालाबाजारी करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व देश में मुद्रा की मांग का गलत फायदा उठा रहे हैं। विडंबना यह है कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा नोट में इस्तेमाल होने वाले आयातित कागज और नकली नोट छापने में शामिल ऑपरेटरों पर लगातार कार्रवाई के बावजूद यह गंभीर समस्या बनी हुई है। यह न केवल नकली मुद्रा के बढ़ते खतरे को रेखांकित करता है, बल्कि राष्ट्रविरोधी तंत्र की सुनियोजित साजिश का भी पदार्पाश करता है। जबकि 2016 में नोटबंदी के ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार, कालेधन और नकली नोटों के खिलाफ लड़ाई उनकी प्राथमिकताओं में है। नोटबंदी केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला साहसी एवं युगांतरकारी कदम था।

आज भारत को सिर्फ बाहरी सीमाओं पर नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है, नकली मुद्रा के खिलाफ, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ और राष्ट्रविरोधी मानसिकता के खिलाफ। इसमें विजय तभी संभव है, जब हम सब डिजिटल भारत के निर्माण में सहभागी बनें। नकली मुद्रा का मुद्दा केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है। यह एक प्रकार का आर्थिक आतंकवाद है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, महंगाई को बढ़ाना, काले धन को बढ़ावा देना और आतंकवाद को वित्त पोषण देना है। ये नकली नोट अधिकतर सीमापार से संचालित तंत्रों द्वारा भारत में भेजे जाते हैं, जो भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह राष्ट्र के विरुद्ध षड़यंत्र, साजिश एवं बड़े खतरों को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि नकली नोट बाजार में असली नोटों के साथ मिलकर मुद्रा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आम नागरिक अनजाने में इन्हें ले लेता है और आर्थिक नुकसान उठाता है। यह काले धन और आतंकवाद को पोषित करता है। नकली नोट सरकारी योजनाओं की निष्पक्षता और वितरण प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल क्रांति न केवल नकली नोटों को नियंत्रित करने का बल्कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नेस्तनाबूद करने का सशक्त माध्यम है। यह मोदी की दूरदृष्टि एवं नये भारत-विकसित भारत के विजन की विजय है, उनके ही विचारों में डिजिटल लेन-देन केवल तकनीक नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। आज के भारत की अर्थव्यवस्था एक निर्णायक दौर से गुजर रही है। डिजिटल ग्राम योजना, ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता अभियान यानी तकनीक को गाँव और गरीब तक पहुँचाने की पहल है। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नकली नोटों की बाढ़ एक अदृश्य आतंकवाद बनकर देश की अर्थव्यवस्था, समाज और सुरक्षा को चुनौती दे रही है। निस्संदेह, हाल के वर्षों में, भारत ने नकली नोटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने व काले धन पर रोक के लिये डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिये अपनी स्थिति खासी मजबूत की है। सरकार की सोच है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए नगद लेन-देन को हतोत्साहित किया जाए।

इस संकट की घड़ी में डिजिटल लेन-देन एक बड़ी राहत और समाधान बनकर उभरा है। यूपीआई, भीम मोबाइल वॉलेट्स, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट्स जैसे साधन नकली नोटों की समस्या को जड़ से समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं। डिजिटल लेन-देन के लाभ ही लाभ है, पूर्ण पारदर्शिता यानी हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। कर चोरी, हवाला, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी काली प्रवृत्तियाँ समाप्त होती है। नकली मुद्रा की संभावनाओं पर विराम लगता है, जिससे राष्ट्र-विरोधी तत्वों के षड़यंत्र एवं साजिशें नाकाम होती है। लेन-देन सेकंडों में पूरा होता है और उनमें सरलता भी रहती है। पासवर्ड आधारित सुरक्षा व्यवस्था से लेन-देन सुरक्षित रहता है। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचता है, पैसा सीधे उनके खातों में पहुँचता है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड, और कार्ड से भुगतान की शिक्षा देने की मुहिम चलाई है। इसका असर यह है कि आज भारत यूपीआई ट्रांजैक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। डिजिटल इंडिया गरीब को ताकत देता है, मिडल क्लास को सुविधा देता है और राष्ट्र को मजबूती देता है। भारत की असली शक्ति अब डिजिटल प्रचलन बन रही है, जहाँ एक बटन से करोड़ों का ट्रांजैक्शन सुरक्षित होता है। मोदी की डिजिटल क्रांति ने भारत को इक्कीसवीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मजबूत आधार दे दिया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस डिजिटल युद्ध में सहभागी बनें, नकली नोटों को ना कहें, डिजिटल लेन-देन को अपनाएं। यही राष्ट्रभक्ति है, यही समय की माँग है। संदिग्ध नकदी की सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें। नकली नोटों की पहचान करना सीखें और दूसरों को भी जागरूक करें। निश्चित ही जहाँ नकली नोट देश की आत्मा को खोखला करते हैं, वहीं डिजिटल मुद्रा राष्ट्र की नींव को मजबूत करती है।

निस्संदेह, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत के आर्थिक लेन-देन तंत्र में क्रांति ला दी है। भुगतान के तमाम विकल्पों ने भारतीय नागरिकों के आर्थिक व्यवहार को बहुत आसान बना दिया है। हालांकि, अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो डिजिटल माध्यम से लेन-देन में परहेज करते हैं। निस्संदेह, नकदी पर उनकी निर्भरता का मूल कारण डिजिटल शिक्षा का अभाव ही है। साथ-ही-साथ डिजिटल भुगतान से जुड़े घपल्ले एवं घोटाले भी है। साथ ही इसके कारणों में भ्रष्टाचार और कर चोरी की नीयत भी शामिल है। ऐसे में सरकार को डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में रचनात्मक पहल करनी चाहिए। वहीं दूसरी आर्थिक अनियमितताएं करने वाले तत्वों से भी सख्ती से निबटा जाना चाहिए। हालांकि, दो हजार के नोट अब प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनका कानूनी आधार बना हुआ है। इस दिशा में यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नकली मुद्रा के पीछे कुछ संगठित राष्ट्रविरोधी शक्तियाँ सक्रिय हैं। पाकिस्तान स्थित आईएसआई और उसके सहयोगी संगठनों पर पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वे नकली भारतीय मुद्रा भारत में भेजकर आतंकवाद और अलगाववाद को आर्थिक समर्थन देते हैं। देश की सरकार ने डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार लिंकिंग, और यूपीआई जैसी क्रांतिकारी योजनाओं के जरिए नकदी पर निर्भरता घटाने का प्रयास किया है। लेकिन यह लड़ाई अकेली सरकार नहीं जीत सकती।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था का सरकारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के मार्ग में अभी तमाम बाधाएं विद्यमान है। यह और भी बड़ी चिंता की बात है कि नोटबंदी के आठ साल बाद भी रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बना हुआ है। निस्संदेह, डिजिटल युग में भी नकदी ही राजा है मानने वालों को रोकने के लिये जांच और कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। साथ ही इस दिशा में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश में लगी विदेशी ताकतों की नकली करेंसी के प्रसार में कितनी बड़ी भूमिका है। विगत में पाकिस्तान से ड्रग मनी व आतंकी संगठनों की मदद के लिये नकली करेंसी के उपयोग की खबरें सामने आती रही हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

ईरान को लेकर भारतीय दूतावास की सख्त एडवाइजरी, जब तक एकदम जरूर न हो यात्रा न करें

(एजेन्सी)।

ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नया परामर्श जारी किया है, जिसमें भारतीय नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है। दूतावास ने एक्स पर जारी अपने परामर्श में, उनसे क्षेत्र में बदलते हालात पर सावधानीपूर्वक विचार करने को कहा है। दूतावास ने ईरान में पहले से मौजूद लोगों से भी मध्य पूर्व क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहने को कहा है और कहा है कि वे ईरान छोड़ने के लिए वाणिज्यिक उड़ानों और उपलब्ध नौका सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

पिछले कई हफ़्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर-जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम परामर्शों का पालन करें। जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहाँ से जाने के इच्छुक हैं, वे अभी उपलब्ध व्यावसायिक उड़ान और नौका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह परामर्श क्षेत्र में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में जारी किया गया है, जो इजराइल, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य तनातनी की श्रृंखला से और भी बढ़ गया है।

पिछले महीने, इजराइल ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था, जिसमें नतांज और फोर्डो सहित ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जवाब में, ईरान ने इजराइली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। इजराइल के समर्थन में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 22 जून को फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित प्रमुख ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की। ईरानी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमले शुरू किए, जिसमें इजराइली कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रमुख ठिकानों और कतर में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया।

सेंसेक्स, निफ्टी में शुरूआती कारोबार में गिरावट

(एजेन्सी)।

वैश्विक शेयर बाजारों में सुस्त रुख के अनुरूप बुधवार को शुरूआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क संबंधी अनिश्चितता के कारण भी निवेशक बाजार से दूर रहे।

बीएसई सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 103.16 अंक की गिरावट के साथ 82,467.75 अंक पर और एनएसई निफ्टी 56.75 अंक फिसलकर 25,139.05 अंक पर रहा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इटर्नल (पूर्व में जोमैटो), बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। ट्रेंट, टेक महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स और एचडीएफसी बैंक के शेयर में तेजी रही। एशियाई बाजारों में जापान का निक्की 225, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट नुकसान में रहे जबकि हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहा।

अमेरिकी बाजार मंगलवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 68.85 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 120.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बनें माता-पिता

(एजेन्सी)।

बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अब एक बच्ची के माता-पिता बन गए हैं। इस जोड़े ने 15 जुलाई, 2025 को मुंबई के रिलायंस अस्पताल में अपनी बेटी का स्वागत किया। कियारा और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं, और इस खबर को प्रशंसकों, दोस्तों और परिवार से प्यार और आशीर्वाद मिला है।

सिड-कियारा के माता-पिता के अस्पताल में प्रवेश की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आज सुबह, नए माता-पिता ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपने प्रशंसकों, दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ यह खुशखबरी साझा की।

एक प्रशंसक ने कहा, "आप दोनों को बधाई। आशीर्वाद के साथ अपने माता-पिता बनने का आनंद लें। आपके प्यारे बच्चे को आशीर्वाद मिले।" एक अन्य ने टिप्पणी की, "आपका बच्चा धन्य हो और हमेशा खुश रहे।" तीसरे ने टिप्पणी की, "हमें एक और प्यारा सा बच्चा मिला है।" "लगता है कैप्टन विक्रम बत्रा का परिवार पूरा हो गया", "इतने लंबे समय से इंतजार था", "सभी छात्र अब लड़कियों के माता-पिता हैं" जैसी कुछ और प्रतिक्रियाएँ थीं। फरवरी में, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे के मोजे पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर साझा की और कैप्शन दिया, "हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार... जल्द आ रहा है"।

सिद्धार्थ और कियारा पहली बार एक पार्टी में मिले थे और फिर उनका रोमांस उनकी पहली फिल्म "शेरशाह" के सेट पर परवान चढ़ा। इस जोड़े ने कभी भी अपने रिश्ते को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया और 7 फरवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में एक भव्य समारोह में उन्होंने शादी कर ली। हालाँकि दोनों अपनी निजी ज़िंदगी को गुप्त रखना पसंद करते हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर कभी-कभार अपने प्रशंसकों को सरप्राइज देना सुनिश्चित करते हैं। इससे पहले, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला पल साझा किया था जब प्यारे पिल्लों के साथ खेला, खुशी और उत्साह बिखेरा।

भारतीय फुटबॉल की वर्तमान स्थिति को लेकर सुनील छेत्री ने जताई चिंता

(एजेन्सी)।

भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई है। हालांकि, उन्हें उसमें सुधार की उम्मीद भी दिख रही है। बता दें कि, शीर्ष स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग यानी क्रछ को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से खेल जगत चिंतित, आहत और डरा हुआ है। लीग में बेंगलुरु एफसी की ओर से खेलने वाले छेत्री ने कहा कि, उन्हें देश में इस खेल के भविष्य को लेकर आशंकाएं व्यक्त करने वाले फोन कॉल और संदेशों की बाढ़ आ गई है। 40 वर्षीय दिग्गज ने एक्स पर लिखा कि, मुझे सबसे पहले ये चिंता हुई कि मेरे पास खेल का जो समय बचा है उसको मैं कैसे बिताऊंगा। लेकिन कई क्लबों के खिलाड़ियों से बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी समस्या उतनी अहम नहीं है। भारतीय फुटबॉल की वर्तमान स्थिति बहुत चिंताजनक है। मुझे न केवल मेरे क्लब से, बल्कि अन्य क्लबों से भी खिलाड़ियों, स्टाफ सदस्यों, फिजियो, मालिश करने वालों से ढेर सारे संदेश मिले हैं। छेत्री ने कहा कि, भारतीय फुटबॉल पारिस्थितिकी तंत्र में अभी जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है उससे हर कोई चिंतित, आहत और डरा हुआ है। आईएसएल ने आयोजकों और अखिर भारतीय फुटबॉल महासंघ के बीच मास्टर राइट्स एग्रीमेंट के नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता के कारण 2025-26 के सत्र को स्थगित कर दिया है।

स्ट्राइकर दीपिका ने पोलिग्रास मैजिक स्किल अवॉर्ड जीता

(एजेन्सी)। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने एफआईएच प्रो लीग 2024-25 सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने मैदानी गोल के लिए पोलिग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। एफआईएच हॉकी प्रो लीग के 2024-25 सत्र के लिए पोलिग्रास मैजिक स्किल अवॉर्ड के विजेता का फैसला दुनियाभर के हॉकी खेल प्रेमियों के मतदान के आधार पर किया गया। दीपिका ने ये गोल फरवरी 2025 में प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के दौरान किया था। कलिंग स्टेडियम में खेला गया ये मैच निर्धारित समय में 2-2 से बराबर रहा था, जिसके बाद भारत ने शूटआउट में नीदरलैंड को हराया। भारतीय टीम जब दो गोल से पीछे चल रही थी तब दीपिका ने 35वें मिनट में ये अविश्वसनीय गोल किया। उन्होंने नीदरलैंड की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए बायीं ओर से बेहतरीन तरीके से ड्रिबल किया, बेसलाइन को छुआ और एक डिफेंडर की स्टिक के ऊपर से गेंद को आगे निकालकर गोलकीपर को छकाते हुए गेंद को नेट में पहुंचाया। दीपिका ने कहा कि, ये पुरस्कार पाकर मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूं। नीदरलैंड जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गोल करना मेरे लिए सचमुच में विशेष पल था और अब ये सम्मान पाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं अपने साथियों, कोचों, परिवार और दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूं जो हर दिन मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं।

ईवीएम डिमॉन्सट्रेशन सेंटर का उद्घाटन, आम जनता को मिलेगी मशीन की जानकारी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। जमुई अनुमंडल कार्यालय में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के क्रम में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन बुधवार को किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी-सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री नवीन द्वारा किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर में आम लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की जानकारी दी जाएगी। यह सेंटर विधानसभा चुनाव की घोषणा तक नियमित रूप से कार्य करेगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि मतदाता ईवीएम के कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हों और मतदान के दिन किसी प्रकार की शंका या भ्रांति न रहे। जिले के नागरिक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस सेंटर पर जाकर ईवीएम मशीन को समझ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सफलता के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

सांगठनिक समीक्षा बैठक का आयोजन

एसबी ब्यूरो

बेगूसराय नगर। 16 मई को जिला कांग्रेस कार्यालय के प्रांगण में 146 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से सम्बंधित सांगठनिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर से भेजे गये पर्यवेक्षक पंकज उपाध्याय, विधायक मध्य प्रदेश, गर्वित सिंघवी उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस दिल्ली के साथ जिलाध्यक्ष अभय सिंह सर्जन, पूर्व विधायक अमिता भूषण सहित वरिष्ठ नेता, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखी।

आम कार्यकर्ताओं का एक स्वर में मत रहा कि बेगूसराय विधानसभा कांग्रेस की प्रतिष्ठा की सीट रही है, कई मिश्रित कारणो से अल्प वोटों जो पिछले बार हार का सामना करना पड़ा था। उन गलतियों को मेहनत से दूर कर हम जीत की ऐसी पटकथा लिखने को तैयार हैं जो इतिहास बनेगा। पर्यवेक्षक ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेगूसराय जिला और यहां की सीट पर दल ही नहीं दल से उपर भी लोगों की नजर है। बेगूसराय का इतिहास कांग्रेस के लिए गौरवशाली रहा है, अगर यहां के कार्यकर्ताओं ने यही जोश बरकरार रखा तो वास्तव में बेगूसराय विधानसभा इतिहास रचने का काम करेगा। जरूरत है एकजुटता के साथ पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की।

जिलाध्यक्ष ने भी बेगूसराय की सांगठनिक गतिविधियों से पर्यवेक्षक को अवगत कराया। अपने संबोधन में श्रीमती अमिता भूषण ने बेगूसराय विधानसभा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार दर्ज करते हुए कहा कि इस विधानसभा में पार्टी की रणनीति के अनुसार चलाए जा रहे कार्यक्रम की स्थिति संतोषप्रद है। हर घर झंडा माय बहिन मान योजना बीएलओ का चयन सभी कार्य समय से हो रहा है। उन्होंने अगले तीन महीने कार्यकर्ताओं से इस मेहनत को बरकरार रखने का आह्वान किया।

बैठक में राजकुमार, प्रखंड अध्यक्ष धर्मराज सहनी, विजय कुमार सिंह, रामस्वरूप पासवान, रामपदारथ यादव, पंचायत अध्यक्ष अशरफ, शंभू साह, अनिल कुमार, पप्पू सिंह, बालेश्वर महतो, मुस्तफा, अभिजीत कुमार, डावर खा, अशोक कुमार, मो. इमरान, संजीव सिंह, रिषभ कुमार, रामरिझन हजारी, अर्जुन पोद्दार, मुकेश सिंह, सुरेंद्र महतो, सुरेस राय, नरेश महतो, जावेद, रामविलास सिंह, सुनील सिंह, संजीव सिंह, अमित शाह, साबर कुमार, जय प्रकाश साह, मोहित सिंह, रामपदार्थ यादव, जफर शेख, राममूर्ति सिंह, रामप्रकाश सिंह, आर्यन ठाकुर, कुमार रत्नेश टुल्लू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचलन नगर अध्यक्ष ब्रजेश कुमार प्रिंस एवं चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से किया।

जयपुर में अमित शाह की सभा को लेकर टोंक भाजपा की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया

संजना भारती संवाददाता/एस रहमान

टोंक। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा संवाद केंद्र पर 17 जुलाई को दादिया में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने बताया कि देश के गृह व सहकारिता मंत्री जयपुर के दादिया गांव में सहकार एवं रोजगार उत्सव में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने बताया कि टोंक जिले से भी 75 बसों से लगभग 4500 लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके लिए पार्टी ने सभी विधानसभा प्रभारी एव मंडल स्तर पर एक संयोजक दो सहसंयोक नियुक्त किए है। प्रत्येक बस पर भी प्रभारी नियुक्त किए है। टोंक, देवली, उनियारा, निवाई, पीपलू विधानसभा के कार्यकर्ता की भोजन व्यवस्था बजरी पोस्ट गुन्सी निवाई एवं टोडा मालपुरा के कार्यकर्ताओं की भोजन व्यवस्था चौसला में की गई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास के वादों और केंद्र सरकार के अभियानों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बैठक के पश्चात एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया।

खानपुर प्रखंड क्षेत्र में मिथिला का पावन पर्व नाग पंचमी के अवसर पर विषहर माता के पुजारी ने विषैले सर्प को हाथ से पकड़ कर पूजा अर्चना के बाद दिखाया खेल तमासा

संजना भारती संवाददाता
अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर। देवो के देव महादेव का पवित्र सावन माह कृष्ण पक्ष में मिथिला का नव विवाहिता बहन बेटियों ने नाग पंचमी पर्व में 15 दिनों के लिये व्रत रख कर नाग देवता का पूजा अर्चना करती है।जो मिथिला के बहन बेटियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण नाग पंचमी पर्व है।

वही बताते चले कि नाग पंचमी पर्व के अवसर पर खानपुर प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों जगह विषहर माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों के पुजारी ने नाग पंचमी पर्व के अवसर पर अपने हाथों से विषैले सर्प को पकड़ कर पूजा अर्चना करते हुऐ हजारो लोगो की जुटी भीड़ में विषैले सर्प को अपने गर्दन व हाथ से पकड़ कर खेल तमाशा देखते।वही नाग पूजा देखने आये लोगो यह भी कहता है कि जिस विषैले सर्प को देख कर लोग डर कर भाग जाते है। जो कही काट न ले। उस विषैले सर्प को विषहर के पुजारी ने अपने हाथों से पकड़ कर गर्दन में लपेट कर खेल तमासा दिखाते है। यह तो विषहर माता की कृपा है।

वही बतादे की नाग पंचमी पर्व के अवसर पर खानपुर बाजार स्थित पूजा टेन्ट हाउस के सामने पोखर के बगल में विषहर मंदिर व माँ काली मंदिर परिसर में पुजारी सीताराम पंडित व रामदेव भगत ने अपने हाथों से विषैले सर्प को पकड़ कर मंदिर में दूध लाबा चढ़ा कर पूजा करते हुऐ विषहर माता के पुजारी सीताराम पंडित व रामदेव भगत एंव रामविलास महतो सहित दर्जन भर स्थानीय लोगो ने विषैले सर्प को अपने गर्दन व हाथ में लेकर नाग पूजा देखने आये लोगो के बीच खेल तमासा दिखाये। तथा विषैले सर्प को लेकर खानपुर बाजार में भ्रमण किया।वही समस्तीपुर बहेरी मुख्य पथ के मनवारा गाँव स्थित मोइन के किनारे विषहर मंदिर के पुजारी रामचन्द्र भगत ने दर्जनों विषैले सर्प को अपने हाथों से पकड़ कर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नाग पूजा देखने आये हजारो लोगो के बीच खेल तमासा दिखाये। विषहर पूजा को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पूजा टेन्ट के मालिक रामविलास महतो, कैलास महतो, भवेश महतो, किसुन प्रसाद, रामलखन महतो, सीताराम पंडित सहित अन्य लोगों भी शामिल थे।

सामाजिक समरसता की पार्टी है जननायक लोक दल: रवि

एसबी ब्यूरो

बेगूसराय। जननायक लोक दल गरीब-गुरबो की पार्टी है सामाजिक समरसता को लेकर पार्टी का अभियान लगातार जारी है। यह बातें जननायक लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 243 सीटों पर उनकी दावेदारी होगी। उन्होंने कहा कि जननायक लोक दल के प्रति लोगों की लगातार जागरूकता बढ़ी है। पार्टी संगठन में जुड़ने के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत बूथ लेवल कमेटी को मजबूत प्रदान किया जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

जननायक लोक दल का लक्ष्य समाज के वंचित नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी लोगों को जोड़ना और उन्हें अधिकार दिलाना।

हरियाणा पत्रकार संघ करनाल की कार्यकारिणी घोषित, राजकुमार प्रिंस ने किया पदाधिकारियों के नामों का ऐलान

जिला स्तर पर जल्द होगी पत्रकारों की अहम बैठक

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा पत्रकार संघ की जिला करनाल इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार प्रिंस ने आज जिला कार्यकारिणी, मंडल संयोजकों और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की। इस घोषणा से जिलेभर के पत्रकारों में उत्साह का माहौल है।

संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संरक्षक पद पर संदीप साहिल, देवेंद्र गांधी और कमल मिड्ढा को नियुक्त किया गया है। वहीं हरीश चावला, के.के. संधू, हरि किशन आर्य, गुलशन मोंगिया और विजय कांबोज को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव पद की जिम्मेदारी आशुतोष गौतम और हिमांशु नारंग को सौंपी गई है, जबकि सचिव पद पर दीपक कांबोज, विकास मेहला, नरेंद्र लाठर, प्रदीप मेहता और जगदीप मराठा को नियुक्त किया गया है।

सह सचिव के रूप में वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत वर्मा, रचना तलवार, इशिका ठाकुर और सुभाष गुरेजा को जिम्मेदारी दी गई है। कोषाध्यक्ष मुकुल सतीजा और इवेंट मैनेजर की भूमिका में विनय बंसल को चुना गया है।

संयोजक पद पर दिलबाग लाठर (घरौंडा), सतीश जोशी (नीलोखेड़ी), जसबीर राणा (असंध) और सुरेश अनेजा (इंद्री) की नियुक्ति की गई है। जिला कार्यकारिणी में वरिष्ठ पत्रकार बिशपाल राणा, कमलदीप, संदीप रोहिला, मीनाक्षी, भगवान दास, जयपाल बंसल, हरीश मदान, गुरनाम सिंह, विवेक राणा, रोहित लामसर, पीयूष भुम्बर और मेनपाल कश्यप शामिल किए गए हैं।

राजकुमार प्रिंस ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं और हितों को प्राथमिकता देते हुए संघ हर मोर्चे पर सक्रिय रहेगा। बहुत जल्द जिला स्तर पर एक अहम बैठक आयोजित कर आगामी योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में शामिल सभी सदस्य लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ग्रीन ऊर्जा की ओर कदम: 4 जिलों की अनाज मंडियों में 24.5 करोड़ रुपये की लागत से लगेंगे सोलर प्रोजेक्ट, बिजली खर्च में होगी सालाना 3.5 करोड़ रुपये की बचत

पंजाब भर की मंडियों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे: हरचंद सिंह बर्सट

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़/मोहाली। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पंजाब मंडी बोर्ड ने जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर और लुधियाना की विभिन्न मंडियों में 24.5 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। इस पर्यावरण-अनुकूल पहल से बिजली खर्च में प्रतिवर्ष लगभग 3.5 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है। यह जानकारी पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन स हरचंद सिंह बरसट ने दी।

स बरसट ने मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनाज मंडियों, फल एवं सब्जी मंडियों, मार्केट कमेटियों और ई-नाम से संबंधित चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। चेयरमैन ने आगे बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड राज्य की मंडियों में 50,000 से अधिक पौधे लगाएगा। यह प्रयास राज्य की मंडियों और उनके आसपास हरियाली बढ़ाने तथा पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने हेतु मंडी बोर्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स बरसट ने अधिकारियों को तलवंडी साबो स्थित गेस्ट हाउस के नवीनीकरण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि इसे किसान भवन, चंडीगढ़ की तर्ज. पर संचालित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड की आवासीय कॉलोनियों में खाली पड़े मकानों को आवंटित करने की तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडियों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत पटियाला क सनौर मंडी में बूम बैरियर लगाए गए, जिससे मंडी फीस में बढ़ोतरी हुई। इस परियोजना की सफलता को देखते हुए इसे राज्य की अन्य मंडियों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। स बरसट ने अधिकारियों को राज्य की मंडियों में हुए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने और सब्जी मंडियों की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंडियों में उत्पन्न होने वाले कचरे के दैनिक निष्पादन को सुनिश्चित किया जाए तथा इस बायो-वेस्ट से आय सृजन हेतु कदम उठाए जाएं।

बोर्ड की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए चेयरमैन स बरसट ने बताया कि मंडी बोर्ड को इस वर्ष अब तक 842 प्लॉटों की ई-नीलामी से 373 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की मंडियों के कवर शेडों को ऑफ-सीजन के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु खोले जाने की पहल को व्यापक सराहना मिली है, जिससे अब तक एक करोड़ रुपये की आय हुई है। यह पहल मंडियों के मौजूदा बुनियादी ढांचे के उपयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में मंडी बोर्ड के प्रयासों को दर्शाती है।

राज्यव्यापी अभियान के तहत गुरदासपुर ज़िले में दो बाल विवाह रोके गए: डॉ. बलजीत कौर

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। बाल विवाह रोकथाम अभियान के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत हाल ही में गुरदासपुर ज़िले में बाल विवाह के दो मामलों को सफलतापूर्वक रोका गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई (डी सी पी यू), सीडीपीओ, बाल कल्याण समितियों और चाइल्ड हेल्पलाइन टीमों द्वारा समन्वित और तेज कार्रवाई करते हुए ये दोनों बाल विवाह-गांव सहाणे चक्क (ब्लॉक कलानौर) और गांव गाधियां पन्याड (ब्लॉक गुरदासपुर) में रोके गए।

डॉ. बलजीत कौर ने यह स्पष्ट किया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है। जैसे ही संभावित बाल विवाह की जानकारी मिली, तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोनों परिवारों को कानून, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बाल विवाह की घटनाओं को जड़ से समाप्त करने हेतु लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि पंजाब को एक प्रगतिशील और बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य वाला राज्य बनाया जा सके।

परिवार के सदस्यों ने अधिकारियों को सहयोग का भरोसा दिया और बच्चों के विवाह को कानूनी उम्र तक के लिए स्थगित करने की सहमति भी जताई। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए परिवारों और ग्रामीणों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी भी दी गई।

डॉ. बलजीत कौर ने आम जनता से अपील की कि वे जागरूक रहें और यदि अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम जिला में 188 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में जिला के विकास के लिए 188 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे लोक निर्माण विश्रामगृह में पहुंचे। जहां उन्होंने पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 55 करोड़ 5 लाख 67 हजार की लागत से बनाए गए पचगांव से फर्रुखनगर वाया जमालपुर डबल लेन मार्ग तथा 13 करोड़ 18 लाख 83 हजार रुपए की लागत से हेलीमंडी, फर्रुखनगर वाया मेहचाना मार्ग के नवीनीकरण का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने सोहना विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए की लागत से निर्मित जीए रोड से अलीपुर हरिया हेड़ा मार्ग तथा रायसीना गांव में बने मंदिर रोड का उद्घाटन किया। उन्होंने 32 लाख 63 हजार की लागत से निर्मित बीपीडीएस रोड से नुनेरा, 28 लाख 26 हजार रुपए की लागत से पूर्ण हुए लोह सिंघानी से चमनपुरा रोड का भी उद्घाटन किया। इसी क्रम में सोहना विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ 34 लाख 53 हजार की राशि से बनने वाले जीए रोड से धुमसपुर वाया नयागांव तथा 16 करोड़ 56 लाख 79 हजार की राशि से बनने वाले सोहना-अभयपुर-लोहटकी-खेडला तथा दमदमा से रिठौज सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया।

विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा चंदू बुढेड़ा में 63 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 100 एमएलडी क्षमता की नवीन जल परिशोधन यूनिट-4 का उद्घाटन किया।

इस परियोजना के माध्यम से गुरुग्राम के 81 से 115 तक 34 सेक्टरों में रहने वाले 4.5 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यहां नहरी पानी का संशोधन कर उसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस यूनिट के तैयार होने से लक्ष्मण विहार, तिकोना पार्क, न्यू कालोनी, ज्योति पार्क, अर्जुन नगर, सेक्टर 12 ए, दयानंद कालोनी आदि में सौ लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन पानी की सप्लाई हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने जिला के शिक्षागत ढांचा को मजबूत करने के लिए आज समग्र शिक्षा अभियान के तहत बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव दौलताबाद में 5 करोड़ 3 लाख 89 हजार तथा गाँव धनवापुर में 2 करोड़ 39 लाख 56 हजार, सोहना में 4 करोड़ 70 लाख 30 हजार तथा गांव घामड़ोज में 3 करोड़ 40 लाख 59 हजार एवं गांव सिलानी में 3 करोड़ 12 लाख 87 हजार की लागत से बनने वाले नए स्कूल भवनों की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डी.एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, डीसी अजय कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में लगा पर्यावरण संरक्षण का बीज: भारद्वाज

हर गांव में 10 पौधे लगाने का लक्ष्य, कुल 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। गांव शामगढ़ में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष संदेश दिया गया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ प्रदेश महामंत्री सुनील वत्स और पूर्व जिलाध्यक्ष विनय संधू गगसीना भी विशेष रूप से मौजूद थे।

राजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पर्यावरण संकट के इस दौर में पेड़ ही पृथ्वी के असली रक्षक हैं। उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 51 लाख छायादार व फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रत्येक गांव में 10-10 पौधे लगाए जा रहे हैं और किसानों व ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जैसे गाय को मां का दर्जा दिया गया है, वैसे ही पेड़ भी संजीवनी देने वाले जीवनदायक स्रोत हैं। पेड़-पौधे न सिर्फ छाया, लकड़ी और फल देते हैं बल्कि ऑक्सीजन जैसे अमूल्य तत्व भी प्रदान करते हैं।" मिक्स खेती की वकालत करते हुए भारद्वाज ने कहा कि किसान यदि फसलों के साथ पौधों की मिलीजुली खेती करें, तो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा सकते हैं।

इस अवसर पर स्कूल स्टाफ, ग्रामीण और विद्यार्थी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलकर पौधारोपण किया और अभियान में भागीदारी निभाई।

बिना मान्यता के चल रहे 250 प्ले स्कूलों को भेजा नोटिस

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में बिना मान्यता चल रहे करीब 250 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं और जल्द से जल्द मान्यता लेने के निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे प्ले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शशिबाला ने बताया कि इन प्ले स्कूलों में तीन से पांच वर्ष के बच्चों के दाखिले किए गए हैं। बिना अनुमति के छोटे बच्चों को दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे करीब 250 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें नियमानुसार सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से मान्यता लेनी होगी। बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्ले स्कूलों की मान्यता जरूरी है। गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी शशिबाला ने बताया कि प्ले स्कूल भवन सुरक्षित, स्वच्छ व बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। जिसमें पर्याप्त क्षेत्रफल, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था और अग्निशमन से संबंधित उपकरण का होना जरूरी है। इसके अलावा सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन तथा पोक्सो एक्ट का शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके बिना प्ले स्कूल संचालित करना कानूनी जुर्म है। इसकी मान्यता के लिए एनसीपीसीआर की गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, '**संजना भारती**' को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।
संपर्क करें: 9871221635

प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एसडीएम को दिया ज्ञापन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। हिसार में प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन असंध ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की। एम एम पब्लिक स्कूल के निदेशक आर.वी भारद्वाज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की हत्या कर दी गई।

इस घटना के विरोध में प्रदेश भर के निजी स्कूलों ने स्कूल बंद रखे है और सभी जगह ज्ञापन दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि हस्पतालों और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून की तर्ज पर शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। जिससे त्वरित न्याय प्राप्त हो सके।

विद्यालय से अनुशासनहीनता के आरोप में बच्चों के निष्कासन के नियमों को सरल बनाकर विद्यालय प्रशासन को अधिकार दिए जाए ताकि विद्यालयों में अनुशासन कायम रखा जा सके। विवेकानंद विद्या निकेतन के प्रबंधक मोहिंदर श्योकंद ने कहा कि गुरु का सम्मान इस देश की परंपरा रही है। अभिभावक अपने बच्चों को समझाए और विद्यालय का सहयोग करें। आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक रिछपाल राणा ने कहा कि गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता है और इस रिश्ते को बरकरार रखा जाए। स्कूलों में लगातार हो रहे हमलों को लेकर प्रशासन को अब सख्त कदम उठाने होगें। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा देना ही उनका कार्य नहीं, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्कूलों में शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून बनाकर तुरंत लागू किए जाएं। ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। इस अवसर पर जेपीएस अकादमी के प्रिंसिपल मोहन सिंह, डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सुखपाल सिंह मान, सर्वजीत सिंह, सियाराम शर्मा, प्रवीण हुड्डा, नरेश कुमार सहित अन्य स्कूल संचालक मौजूद रहे।

हल्की बारिश से राजौंद की सड़क बनी तालाब

दुकानदारों का धंधा चौपट-राहगीर, विद्यार्थी परेशान

राजौंद-कैथल मार्ग की हालत खस्ता। (छाया: एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद क्षेत्र में लगातार हो रही हल्की बारिश से राजौंद की सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। कैथल-असंध मार्ग व जींद-पूंडरी मार्ग पर स्थित राजौंद नगर की सड़को की हालत बद से बद्तर हो गई है। राजौंद में कैथल-असंध मार्ग पर डिवाइडर के एक तरफ जहां सिवरेज पाइपलाइन दबाने का कार्य चल रहा है। वहीं डिवाइडर के दूसरी ओर वन-वे मार्ग पर ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। सड़क पर अनगिनत गहरे गड्ढे बने हुए हैं जो पानी व कीचड़ से भरे हुए रहते हैं। इसी मार्ग से होकर शहीद सियाराम संस्कृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं, राजकीय कॉलेज के विद्यार्थी, आईटीआई के विद्यार्थी, प्राथमिक पाठशाला हरिजन बस्ती के विद्यार्थी पानी व कीचड़ में लथपथ होकर गुजरने को मजबूर है।

राजौंद-असंध मार्ग पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नपा कार्यालय, विभिन्न बैंक, पुलिस थाना, बीडीओ कार्यालय, डाकखाना, तहसील कार्यालय, सरकारी अस्पताल, पशु हस्पताल, सीएससी सैंटर, नहरी विभाग कार्यालय, घरेलू गैस कार्यालय, पैट्रोल पंप, पैक्स, फूड सप्लाई कार्यालय जाने के लिए जरूरतमंद नागरिकों को कीचड़, दलदल, पानी से भरे हुए गहरे गढ़ों में से पैदल, दो पहिया वाहन, साइकिल से जाना पड़ता है। पानी, कीचड़ से भरे गड्ढों वाले मार्ग से यात्रा करना जान जोखिम में डालने वाला प्रतीत होता है। मार्केट यूनियन प्रधान भीम सिंह राणा व महाराणा प्रताप मार्केट यूनियन प्रधान सन्नी शर्मा ने बताया कि मुख्य मार्गों पर बनी हुई दुकानों के कारोबारियों के व्यापार धंधे ठप हो गए हैं। ग्राहक दुकानों में आने से कतराते हैं। दुकानों के आगे बने खंडों में पानी व कीचड़ रहता है। चलते हुए वाहनों से कीचड़ युक्त पानी की छाल लगती है, तो दुकानों के अंदर भी कीचड़ दलदल पानी पहुंच जाता है। जिससे नगर के दुकानदारों में भारी आक्रोश है। प्रधान भीम सिंह राणा व सन्नी शर्मा ने बताया कि सिवरेज पाइपलाइन दबाने वाले ठेकेदार की लापरवाही का हजार्ना राजौंद के नागरिक, स्कूल जाते विद्यार्थी, राहगीर भुगतने को मजबूर हैं।

बताया गया कि ठेकेदार को सिवरेज पाइपलाइन दबाने से पहले वैकल्पिक मार्ग तैयार करना चाहिए था। ठेकेदार को डिवाइडर के दूसरी ओर जहां से वाहन प्रतिदिन गुजर रहे हैं उस मार्ग को चलने के लायक बनाना चाहिए था। लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही के चलते नागरिकों की सुरक्षा व सुविधा का ख्याल नहीं रखा।

मार्केट यूनियन प्रधान भीम सिंह राणा व सन्नी शर्मा, दुकानदारों व नागरिकों तारसेम शर्मा, प्रताप प्रजापति, सुरेश कुमार, पवन, निर्मल सिंह, नवाब सिंह, सेमी लाल, राहुल, हेपपी, काला राम, मोहन लाल, नरेश सहित अन्य ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी से अपील की है कि नागरिकों, विद्यार्थियों, राहगीरों को आ रही परेशानी का संज्ञान लेकर नागरिकों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजौंद -कैथल मार्ग, राजौंद -पूंडरी मार्ग को नागरिकों के चलने लायक बनाने के लिए ठेकेदार को निर्देश दे। ताकि किसी भी राहगीर, नागरिक विद्यार्थी को जानी माली नुकसान ना हो।

मेन बाजार मार्केट यूनियन राजौंद प्रधान भीम सिंह।

महाराणा प्रताप चौक मार्केट यूनियन राजौंद प्रधान सन्नी शर्मा।

सन्नी शर्मा-प्रधान महाराणा प्रताप चौक मार्केट यूनियन राजौंद

बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को प्राथमिकता से दूर किया जाए: एसडीएम

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। एसडीएम असंध राहुल ने बुधवार को मानसून के चलते शहर के जींद रोड और मुंड रोड क्षेत्र में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम राहुल ने ड्रेन सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पानी की निकासी में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को प्राथमिकता से दूर किया जाए।

एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान हालात पर लगातार नजर बनाए रखें और जहां कहीं भी जल निकासी में रुकावट आए, उसे तुरंत दुरुस्त करें। इस संबंध में एसडीएम असंध राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके संज्ञान में जींद रोड और मुंड रोड पर बारिश के पानी की निकासी नहीं होने की समस्या आई थी। इस वजह से किसानों की फसलों में जलस्तर अधिक हो गया था जिससे फसलें खराब हो रही थी। जिसके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आमजन की समस्या का निवारण करना उनकी प्राथमिकता है।

सांच गांव में किया गया मुफ्त कानूनी सहायता शिविर का आयोजन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मैहला के आदेशानुसार गांव सांच में मुफ्त कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता पवन कुमार और पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को पीसी-पीएनडीटी एक्ट, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुफ्त कानूनी सहायता और नालसा जागृति योजना, 2025 के बारे में जागरूक किया।

पीसी-पीएनडीटी एक्ट, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुफ्त कानूनी सहायता और नालसा जागृति योजना के बारे में किया गया जागरूक

उन्होंने बताया कि भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक समस्या है। आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग कर बेटियों को जन्म से पहले मिटा देना, हमारे समाज के उस पक्ष को उजागर करता है, जहां स्त्री को आज भी बोझ समझा जाता है। भ्रूण जांच के जरिए लिंग पहचान कराकर लड़कियों को गर्भ में ही मार देना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि नैतिक रूप से भी बेहद शर्मनाक है। भारतीय कानून के अनुसार, पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत भ्रूण हत्या एक दंडनीय अपराध है, जिसमें तीन साल की सजा और जुमार्ना हो सकता है। इसके साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कानूनी सहायता टोल फ्री 15100 और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर डा. पवन कुमार, सुरेश कमार सरपंच गांव सांच, अशोक कुमार और उनका सहयोगी स्टाफ और अन्य मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि विधिक सेवा में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, औधोगिक श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, विकलांग व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय तीन लाख से कम हो और अवैध मानव व्यापार के शिकार लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।

नशा मुक्त हो जिला मुहिम

जिला को नशा मुक्त बनाने में समाज को देना होगा सहयोग: एसपी आस्था मोदी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। एसपी आस्था मोदी के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्त हो जिला अभियान के तहत लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को एसआई कर्मबीर, एएसआई ओमप्रकाश, एचसी सुनील कुमार, महिला सिपाही किस्मत, एसपीओ राजपाल तथा एसपीओ प्रदीप कुमार की टीम द्वारा कैथल में विभिन्न स्थानो पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर विद्यार्थियों सहित आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। एसपी आस्था मोदी ने कहा कि इस दौरान पुलिस टीम द्वारा जानकारी दी गई कि नशा न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, बल्कि उसके पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करता है।

विद्यार्थियों को विशेष रूप से नशे से दूर रहकर पढ़ाई, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वे अपने माता-पिता और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। इस अवसर पर पुलिस टीमों ने नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों को काउंसलिंग कर इलाज करवाने के लिए भी प्रेरित किया तथा लोगों से अपील की कि वे अपने आस-पड़ोस में नशा करने वाले या नशा बेचने वालों की जानकारी पुलिस को गुप्त रूप से दें, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। एसपी आस्था मोदी ने कहा कि जिला पुलिस संकल्पबद्ध है कि समाज को नशा मुक्त बनाया जाए और इसके लिए पुलिस प्रशासन हर स्तर पर प्रयासरत है। यह मुहिम तभी सफल होगी जब आमजन भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और अपने स्तर पर भी समाज में जागरूकता फैलाएं।

राज्य-चिह्न का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई: डॉ. सुमिता मिश्रा

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने नागरिकों से भारत के राज्य-चिह्न, जो भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है, का दुरुपयोग न करने की एक कड़ी सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से निजी वाहनों, लेटरहेड और साइनबोर्ड पर इस चिह्न के अनधिकृत प्रदर्शन के विरुद्ध चेतावनी दी है, और इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कृत्य कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत का राज्य चिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह-स्तंभ का एक रूपांतर है। इस प्रतीक चिह्न का उपयोग भारत के राज्य प्रतीक चिह्न (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 और (प्रयोग विनियमन) नियम, 2007 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें 2010 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये कानून भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किए गए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा इसके उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रतीक चिह्न व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक स्थिति या प्रभाव का प्रतीक नहीं है। यह केवल संवैधानिक प्राधिकारियों और सरकारी विभागों के लिए आरक्षित है, जहाँ कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2005 के अधिनियम और 2007 के नियमों के तहत अनधिकृत उपयोग दंडनीय है, जिसमें भारी जुमार्ने और कानूनी कार्यवाही के प्रावधान शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया निदेर्शों का हवाला देते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रतीक चिह्न, राष्ट्रीय प्रतीकों, मुहरों और झंडों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति शुरू की है। इसमें स्कूलों, कॉलेजों और लॉ कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को प्रतीक चिह्न के कानूनी और संवैधानिक महत्व के बारे में शिक्षित करना शामिल है। यातायात पुलिस को वाहनों पर प्रतीक चिह्न के दुरुपयोग की पहचान करने और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता को प्रतीक चिह्न के उपयोग से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में सूचित करें। सरकार दुरुपयोग की रिपोर्टों से तुरंत निपटने के लिए शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन स्थापित करने पर भी काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार राज्य-चिह्न के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक नियामक उपाय तैयार करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित कदमों में अधिक जुमार्ना लगाना, त्वरित अभियोजन और सार्वजनिक एवं सरकारी स्थानों पर नियमित निरीक्षण अभियान शामिल हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा, "प्रतीक चिह्न राष्ट्र की संवैधानिक गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए इसका दुरुपयोग न केवल अवैध है, बल्कि उन मूल्यों का भी अपमान करता है जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है।"

जेल लोक अदालत में 7 बंदियों को मिली रिहाई, कानूनी सहायता के प्रति किया गया जागरूक

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में जिला कारागार करनाल में बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने लोक अदालत की अध्यक्षता की।

इस विशेष लोक अदालत में 8 मुकदमों को रखा गया, जिनमें से 7 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया और संबंधित 7 बंदियों को आवश्यक शर्तों के साथ रिहा किया गया।

इस अवसर पर सीजेएम डॉ. इरम हसन ने जेल में रह रहे बंदियों से संवाद स्थापित कर निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जेल में उपलब्ध सुविधाओं व सेवाओं का निरीक्षण भी किया और सुधारात्मक दृष्टिकोण से बंदियों की समस्याएं सुनीं। डॉ. हसन ने बंदियों को आश्वासन दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और जरूरतमंदों को न्याय दिलवाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर है।